SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR:*

MR. CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy is here. He will arrange everything. ...(*Interruptions*)... Rest assure. ...(*Interruptions*)...

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR:*

SHRI RUDRA NARAYAN PANY:*

श्री सभापति: आप जो बोल रहे हैं, पता नहीं है कि क्या मामला है,आप तो ज़बरदस्ती खड़े हो गए हैं। Please take your seat. I won't allow. Nothing will go on record ...(*Interruptions*)... Question No. 181.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰ और ए॰पी॰डी॰आर॰पी॰ में परिवर्तन

*181. **श्री मोतीलाल वोरा:†**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰) तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए॰पी॰डी॰आर॰पी॰) से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं को अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से इनमें कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) ने वांछित लाभ प्रदान किए हैं।

वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 10,000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 9819 गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत किए गए और 2006-07 में 2.3.2007

*Not recorded.

†सभा में यह प्रश्न श्री मोतीलाल वोरा द्वारा पूछा गया।

तक 22233 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा 7413 पहले से विद्युतीकृत गांवों का भी सघन विद्युतीकरण किया जा चुका है। 39113 गांवों में राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेंचाइजी पहले से मौजूद हैं। फ्रेंचाइजियों की स्थापना से राजस्व संग्रहण बढ़ा है।

मुख्य जहां तक एपीडीआरपी का संबंध है, इसका उद्देश्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, राजस्व संग्रहण में वृद्धि और उपभोक्ता की बेहतर संतुष्टि सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वितरण कंपनियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां, जो 2001-02 में 38.86% थी, वह 2004-05 में 33.83% हो गई। शहर स्तर पर ये हानियां देश के 212 एपीडीआरपी वाले शहरों में 20% से भी कम हो गई हैं तथा इनमें से 169 शहरों ने यह हानि 15% से कम की है। वितरण कंपनियों की सकल वाणिज्यिक हानि (सब्सिडी के बिना), जो 2001-02 में 29,331 करोड़ रुपये थी, वह 2004-05 के दौरान घटकर 22,129 करोड़ रुपये हो गई। टर्न-ओवर के प्रतिशत में वाणिज्यिक हानि, जो 2001-02 में 36.55% थी, वह 2004-05 में 20.70% हो गई।

(ग)और (घ) वर्तमान अनुमोदन आरजीजीवीवाई स्कीम के चरण-1 के लिए 10वीं योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए है। इस स्कीम को 11वीं योजना में जारी रखने के लिए मामला योजना आयोग द्वारा मूल्यांकनाधीन है।

सरकार द्वारा एपीडीआरपी को 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन दिया गया। मंत्रालय ने एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्तमान प्रयासों, विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझावों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने तथा कार्यक्रम के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए श्री पी॰ अब्राहम, पूर्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया था। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

Changes in RGGVY and APDRP

†*181. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Rajeev Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) and Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP) have not yielded desired results;

(b) if so, the reasons therefor;

---

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Motilal Vora.

(c) whether Government are considering to bring about some changes in these schemes in order to make them more meaningful; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaram Yojana (RGGVY) and Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP) have yielded the desired results.

In the year 2005-06 under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaram Yojana, 9819 unelectrified villages were electrified against the target of 10,000 villages and in 2006-07, as on 2.3.2007, 22233 unelectrified villages have been electrified. Besides this, intensive electrification of 7413 already electrified villages has also been completed. Franchisees are in place in 39113 villages already which is meant to ensure revenue sustainability. The revenue collection has increased with the installation of franchisees.

As regards APDRP, its basic objectives are to reduce Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses, improving quality of supply of power, increasing revenue collection and improving consumer satisfaction. The AT&C losses of the State distribution companies at national level were reduced from 38.86% in 2001-02 to 33.83% for 2004-05. At town level, AT&C losses have been brought below 20 per cent in 212 APDRP towns in the country of which 169 towns have brought AT&C losses below 15 percent. Overall commercial loss (without subsidy) of the distribution companies reduced from Rs. 29.331 crore during 2001-02 to Rs. 22,129 crore during 2004-05. The commercial loss in percentage of turnover has reduced from 36.55% in 2001-02 to 20.70% in 2004-05.

(c) and (d) The present approval is for the Phase-I of the scheme, RGGVY for years 2005-06 and 2006-07 of the X-Plan. The scheme is under evaluation by the Planning Commission for its continuation in the XI-Plan.

The APDRP was approved by the Government for implementation during X Plan. The Ministry had constituted a Task Force headed by Shri P. Abraham, former Secretary, Government of India, to assess and analyse the current efforts under APDRP, suggestions made by various agencies

and to suggest restructuring of the programme. The Task Force has submitted its report which is under consideration.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 39113 गांवों में राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेंचाइज़ी पहले से मौजूद हैं और फ्रेंचाइजियों की स्थापना से राजस्व संग्रहण बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्व का संग्रहण कितना बढ़ा है, क्योंकि यह 39113 गांवों में तो यह पहले से ही मौजूद है। दूसरा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: दूसरा नहीं, अभी आप पहले प्रश्न का उत्तर ही सुन लीजिए। अगर सैटिस्फाइड हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रश्न पूछ लेना।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, फ्रेंचाइजी इसलिए बनाया गया कि ईटीएंडसी लॉसिज़ बहुत ही बढ़ रहे थे और जैसा कि अप्रैल 2005 से यूपीए सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इस देश में लाई गई, उसमें पहली कंडीशन यह रखी गई कि इसमें फ्रेंचाइजिज़ होने चाहिए। यह तय किया गया कि उन्हें बल्क में बिजली दी जाएगी और फिर उनके द्वारा वह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पूरे देश में हमारा यह प्रोग्राम चला है, इस फ्रेंचाइज़ के बारे में एक विशेष बात बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि दो दिन पहले ही महिला दिवस था और उत्तराखंड की महिलाओं ने प्रथम नम्बर पर जो डिस्ट्रिब्यूशन में फ्रेंचाइज़ का काम किया है, इससे उन्होंने केवल युवकों को ही नहीं बल्कि सर्विसमैन को भी काम दिया है। पूरे देश में इस पर जोर-शोर से काम चल रहा है। हर जगह पर पहले फ्रेंचाइजिज़ का एग्रीमेंट होता है और तभी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैंने तो यह पूछा है, उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि फ्रेंचाइजियों की स्थापना से राजस्व संग्रहण बढ़ा है, तो राजस्व संग्रहण में कितनी बढ़ोतरी हुई है? दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने इसके लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार के द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एपीडीआरपी के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन दिया गया और इसके सुझावों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने के लिए श्री पी॰ अब्राहम, पूर्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह रिपोर्ट आपके पास प्रस्तुत हुई, जैसा कि आपने कहा कि वह विचाराधीन है, तो उसकी अवधि क्या होगी? क्योंकि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : विचाराधीन की कोई अवधि नहीं होती है।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, कई बार पूछते हुए आप ही इस बात को कहते हैं। इसके स्थान पर या तो वह कहें कि जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री सभापति: जी हां, बस यही कहते हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, श्री पी॰ अब्राहम पावर डिपार्टमेंट के भूतपूर्व सेक्रेटरी हैं और उन्होंने बहुत डिटेल में, हर स्टेट के लोगों के पास जा कर इस पर कार्य किया है। ये जो फ्रेंचाइजिज़ हैं, इनसे बहुत से स्थानों पर मुनाफा हुआ है, अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि यह एक उदाहरण है, जिस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं ने काम किया है ... ।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: उससे एपीआरडीपी की स्कीम भी वहां लगाई गई है और उसकी वजह से लॉसिस भी कम हो गए हैं। मेरे पास डिटेल्ज़ पूर्ण नहीं हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि वर्ष 2004-2005 में जो लॉसिस थे, उनमें तीन प्रतिशत लॉसिस कम हो गए हैं। मैं इतनी ही मालुमात देना चाहूंगा।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the hon. Minister has stated that 22,233 unelectrified villages have been electrified in 2006-07. But he has not mentioned how many villages have been de-electrified all over the country, particularly in the eastern parts of India of Bihar and Orissa. They have been de-electrified. Does the hon. Minister know what is happening? सर, आप डिटेल्स में जाइये।

श्री सभापति: आप आपस में बात मत करिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Is there any place, that had been electrified during the last five years or even ten years, which has now been de-electrified? I would like to know from the hon. Minister.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Mr. Chairman, Sir, I do not have that information. But I have the information that under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, so far, we have electrified 32,052 rural villages. But I do not have the figures of de-electrified villages.

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मंत्री जी फाइंड-आउट करके बता दें।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उसमें पंचायतों को इन्वालव किया है और उससे इनको फायदा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या पंचायतों को भी कुछ कमीशन दिया जायेगा? क्या जो महिलाएं इसके बारे में काम कर रही हैं, उनका इकोनोमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए कुछ दे रहे हैं? दूसरा इलेक्ट्रिफाईड तो कर दिया है, लेकिन क्या वॉल्टेज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप कोई स्कीम बना रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, फ्रेंचाइज की स्कीम में ही यह कल्पना है कि उनको कमीशन मिल जाए। जब उसको बल्क में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जिस स्टेट की यूटेलिटी है, वही उसका कमीशन डिसाइड करते हैं। जिस तरह का विभाग होगा, उसमें उसी तरह का कमीशन दिया जाता है, कहीं ज्यादा कमीशन होता है और कहीं कम कमीशन होता है, लेकिन इसमें काफी फायदा होता है। मैंने भी इसका व्यु ले लिया था, बहुत सी जगहों पर महिलाओं ने काम किया है, अच्छा काम किया है और उसके लिए हम उनको एनकरेज़ करना चाहते हैं। मैं हर बार उनका उदाहरण दे रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण में वे मुख्य प्रोग्राम ले लें, तो यहां से AT&C लॉसिस भी बच जायेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहां से चोरी होती है।

श्री सभापति: उनको यह कैसे पता है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, हमारे देश में विशेषकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो काम हो रहा है, हमारी बहन भी इसके बारे में जो कह रही हैं कि बिजली निर्माण का काम इस देश में कम हो गया है, उसकी वजह से Load density पर बिजली चल रही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पर एक तरह की बिजली मिलनी चाहिए और हम इसकी स्ट्रैंथनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्रीगोपाल व्यास: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक संशोधन किया है कि तीन सौ से अधिक की आबादी वाले ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं जहां पर हजारों गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी कम है और उन हजारों गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। एक तो सरकार ने बिजली की कटौती की है और दूसरे यह संशोधन किया है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस संशोधन को वापिस लेकर ग्रामों में बिजली प्रदान की जाएगी?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, संशोधन को वापिस लेने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आज जिस छत्तीसगढ़ में बिजली की कमी है, इसी तरह से हमारे देश में और तीन-चार प्रांत भी हैं, लेकिन उनमें से छत्तीसगढ़ में बिजली काफी कम हो रही है, लेकिन वहां काफी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोयला ही कोयला है, इसलिए भारत सरकार वहां के लिए प्रयास कर रही है कि वहां पर ज्यादा बिजली निर्माण की यूनिट्स लग जाएं और मुझे भी इस पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सदन में बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ आज डेफेसिट में है, वह आने वाले पांच सालों में सरप्लस में हो जाएगा। इस तरह की वहां स्थिति है और जो ग्रामीण विद्युतीकरण का काम है, अभी-अभी हमने सैंक्शन दे दिया है और जो पिछले सैंक्शन्स दिए थे, उसमें भी बढ़ोत्तरी करके अभी जो पैसा मिला है, उसमें से छत्तीसगढ़ को priority में ले लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीगोपाल व्यास: मान्यवर, तीन सौ ग्राम वाली बात रह गई।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, यह जो योजना अप्रैल 2005 में बनाई थी, तब केवल 300 से ऊपर की आबादी वाले गांवों की ही योजना बनाई गई थी और उसमें हमारे अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेज 1,19,570 थे, लेकिन जब हमने स्टेटों से मांग करके, सब इनफॉर्मेशन मांगी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उसकी स्टडी करके हमें जो रिपोर्ट भेजी है, वह फिगर 1,19,570 से अभी 1,34,246 विलेजेज हो गई है, जो कि बढ़ती जा रही है और तीन सौ से ऊपर की आबादी वाले गांवों की असली बात यह है कि कई जगह जो सौ, दो सौ, ढाई सौ लोग रहते हैं बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनको भी लेने के लिए सरकार विचार कर रही है।

श्री महेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो बिजलीकरण हो रहा है, लेकिन बिजली प्राप्त भी तो हो! वहां पर कनेक्शन तो दे दिए जाते हैं, लेकिन बिजली वहां होती ही नहीं है। उसका क्या किया जाएगा? अभी माननीय मंत्री महोदय, ने कहा कि तीन-चार राज्यों को छोड़कर हर जगह पर बिजली उपलब्ध है। दिल्ली तक में तो बिजली उपलब्ध नहीं है, इस ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है? कनेक्शन करा दिए जाते है, उसके पैसे की वसूली कर ली जाती है, लेकिन बिजली प्राप्त नहीं होती है, इस संबंध में क्या किया जा रहा है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में तीन-चार प्रश्न पूछे हैं।

श्री सभापति: आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, वे उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली, दोनों उदाहरणों को अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में बिजली निर्माण का काम बहुत कम होता हैं। मैं बार-बार कह रहा हू कि वहां कैपेसिटी addition करना बहुत जरूरी है, दिल्ली के लिए तो हमने एक स्पेशल स्कीम लगाई है क्योंकि यह हमारी कैपिटल है। उसके लिए आपने देखा होगा कि गए तीन महीने में बिजली यहां अच्छी तरह से मिल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बिजली मिलने के लिए हमने हरियाणा, छत्तीसगढ़, वहां से बिजली के ज्यादा युनिट मंगा लिए हैं और 2010 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उस वक्त इसको पूर्ण बिजली दी जाएगी, यह भी इंतज़ाम किया है।

श्री सभापति: मतिलाल सरकार, आप पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री बनवारी लाल कंछल: माननीय मंत्री जी, यह भी बताने की कृपा करें कि उत्तर प्रदेश को बिजली देने में क्या सहयोग आप कर रहे हैं?

श्री सभापति: ठीक है, श्री मतिलाल, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... कंछल जी, आप उनको सुनिए।

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the hon. Minister, in his reply, has stated that 22,233 villages have been electrified. My question is this. Sir, you know that if only ten per cent houses are electrified, the village is called 'electrified'. So, from this figure, we do know what is the actual coverage, on an average. Will the hon. Minister tell us what is the coverage in percentage?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Mr. Chairman, Sir, the earlier scheme was that one pole used to go up to the revenue border of the village, and it was treated as electrified. But, today, we have changed the definition. In every village, electricity must go to school, to Gram Panchayat, to dispensary, and all the BPL and Harijan households must be covered under that. They all should get the electricity connection, and, at least, a minimum ten per cent of the houses should be electrified. Then only, it will be treated as electrified.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 182. ...*(Interruptions)*...

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, he has not answered my question. What is the actual percentage. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

Kutir Jyoti Programme

*182. SHRI SITARAM YECHURY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Finance Minister in his budget speech for 2006-07 had stated that all the unelectrified rural BPL households would be provided electricity connection free of charge as per norms of Kutir Jyoti Programme; and

(b) if so, the percentage of BPL households covered under Kutir Jyoti Programme till 2005-06?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.